

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 48/22

GCMS NO 2022/90

1. प्रभूलाल पुत्र गोपी
2. रामधन पुत्र गोपी
- हीरालाल पुत्र गोपी
- रामसहाय पुत्र गोपी
6. हंसा पुत्र गोपी जातियान मीना निवासीयान करेला तहसील व जिला सवाई माधोपुर अपीलांत

बनाम

1. परसराम दत्तक पुत्र श्योराम उर्फ श्योपाल मीना निवासी करेला तहसील व जिला करौली
2. बदरी पुत्र मांग्या मीना
3. लडडू पुत्र श्योनारायण
4. पतासी पुत्री श्योनारायण
5. लोहडया पुत्र बाबूलाल
6. मुकेश पुत्र बाबूलाल
7. काडया पुत्र बाबूलाल
8. सावली बेवा बाबूलाल
9. उगन्ती पुत्री बाबूलाल
10. मुकेशी पुत्री बाबूलाल
11. तुलस्या पुत्र चतरू
12. चिरंजी पुत्र हरगोविन्द
13. रामस्वरूप पुत्र हरगोविन्द
14. शिवचरण पुत्र हरगोविन्द
15. जमना पुत्री हरगोविन्द
16. हरचंद पुत्र मांग्या
17. ग्याना पुत्र मोती
18. नानगा पुत्र मोती
19. देवकरण पुत्र माधो
20. रामजीलाल पुत्र माधो
21. अनिता पत्नि रघुवीर समस्त जातियान मीना निवासीयान ग्राम करेला तहसील व जिला सवाई माधोपुर
22. शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया सवाई माधोपुर
23. शाखा प्रबंधक आई डी वी आई बैंक मानटाउन तहसील व जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 44/18 निर्णय दिनांक 18.5.22 न्यायालय उप जिला कलवण सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री गिराज सिंह गुर्जर

अभिभाषक रेस्पो0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

दिनांक 16.6.2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.5.22 न्यायालय

उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांत/वादीगण द्वारा ख0न0 146 रकबा 0.4300 चाही 3 एवं खसरा न0 186 रकबा 0.4900 चाही 3 कुल किता 2 कुल 0.9200 है0 वार्के ग्राम करेला तहसील सवाई माधोपुर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है। जिसके वादीगण ख0न0 186 रकबा 0.49 है0 चाही 3 पूर्व खसरा न0 108 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा वादीगण की पैतृक खातेदारी व कब्जे काशत में चली आ रही है जिसमें वादीगण ही आराजी ख0न0 186 रकबा 0.49 ऐयर पर काशत करते लगान अदा करते चले आ रहे हैं एवं आराजी ख0न0 146 रकबा 0.4300 ऐयर पर प्रतिवादीगण की पैतृक है जो आज तक उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण ही काबिज काशत कर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे हैं। लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलती से समस्त दोनों आराजीयात की गलत खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम कर दी गई है जिसे वादीगण ख0न0 186 रकबा 0.49 ऐयर को वापिस दुरुस्त कराकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। सम्म 1988 में उक्त खसरा न0 186 पूर्व ख0न0 108 एवं इससे पूर्व ख0न0 105 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा हाल 186 रकबा 0.49 ऐयर वादीगण के पितामह कल्याण वल्द औकार जो कि हमारे वादीगण के पिता गोपी का पिता था की पर्चा दस साला सम्वत 1988 में राहिन दर्ज खातेदार किया हुआ है जबकि प्रतिवादीगण का पिता जेलाल पुत्र ताराकी खातेदारी में मुर्तहीन दर्ज है। लेकिन सेटलमेंट ने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के वक्त वादीगण के पिता गोपी पुत्र कल्याण के मुर्तहीन दर्ज कर दी एवं वाद में मुर्तहीन हटाकर प्रतिवादीगण के खातेदारी दर्ज कर दी जो गलत है। यदि राहिन हटाया गया तो खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए जबकि मुर्तहीन के नाम कर दी इसलिए आराजी ख0न0 186 रकबा 0.49 ऐयर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजी है। जैसा कि सम्वत 2009 से 2021 एवं 2028 से 2029 एवं सम्वत 2031 से 2035 में भी कब्जा गोपी पुत्र कल्लाण का ही बताया है। जो कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण की बजाय सेटलमेंट की गलती से प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज कर दिया । इस कारण वादीगण आराजी ख0न0 186 रकबा 0.49 ऐयर में राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। आराजी ख0न0 146 ही प्रतिवादीगण के नाम अंकन होना चाहिए। प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर वादीगण की उक्त आराजी को रहन एवं विक्रय करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया धमकी दी गई कि उक्त भूमि को लठठ के जोर पर काशत करेंगे एवं बेचान करेंगे। इसलिए वादीगण का वाद पत्र इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 186 रकबा 0.4900 ऐयर बरानी 3 पूर्व ख0न0 105,105 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा ग्राम करेला वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की भूमि है इस कारण वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार अंकन किया जावे एवं प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजी ख0न0 186 में वादीगण के कब्जे काशत में स्वयं या अन्य किसी से

राजस्व अपील प्राधिकारी

सवाई माधोपुर


मदालखत नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील न्यायालय मे पेश की गई है।



अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणों की वृहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून रुयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का सही रूप से अवलोकन नही किया है एवं गलत प्रकार से आदेश दिया जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नही दिया कि वादी/अपीलांट का वाद पत्र बाबत हस्तकरारहक एवं हुक्मइम्तनाई स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती इन्द्राज का पेश किया था जो जबाब एवं तलबी मे चल रहा था। प्रतिवादीगण ने कोई जबाब पेश नही किया एवं आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो चलने योग्य ही नही था। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नही दिया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र एक विशेष परिस्थितियों मे ही गहनता से सुनकर आदेश दिया है जो चलने योग्य नही है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे मात्र वाद हेतुक, मूल्यांकन, विधि द्वारा वर्णन, दो प्रतियों मे वाद पत्र प्रस्तुत पर मनन किया जाता है। वाद पत्र किस विधि से वर्जित था ऐसा कोई उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे नही दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नही दिया कि मात्र एक ही आधार लेकर निर्णय किया है कि दिनांक 2.5.76 को रहन से वागुजास्त करने का नामा० संख्या 95 स्वीकृत हुआ था। उसकी सक्षम न्यायालय मे अपील नही की। यह कोई आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे नही आता है। उक्त नामा० से कोई प्रभाव वादी/अपीलांट पर नही पडता है उससे कोई खातेदारी अधिकार या कब्जा बाबत कोई अधिकार किसी पक्ष का समाप्त नही हुआ है। जो विधि वर्जित नही कहा जा सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.5.22 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को निरस्त कर वादीगण के वाद पत्र को पुनः सुने जाने हेतु आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पों के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम करेला मे स्थित भूमि खसरा न० 146 रकबा 0.43 है० खाता संख्या 83 जमाबंदी सम्वत 2073-76 मे रेस्पों के पिता के नाम दर्ज है। उक्त भूमि से वादी/अपीलांट का कोई दूर तक का वास्ता संबंध नही है। पूर्व मे जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश की पालना मे दिनांक 2.5.76 को रहन से वागुजास्त करने का नामा० संख्या 95 स्वीकृत हुआ था। वादी/अपीलांट ने वादग्रस्त आराजीयात के बाबत खोले गये नामा० संख्या 95 की किसी भी सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत नही की गई है। वादी/अपीलांट विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त नही है ना ही विवादित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड वादी/अपीलांट के नाम नही है। विवादित आराजीयात की खातेदारी रेस्पों के नाम दर्ज रिकार्ड


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

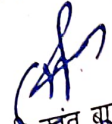
है। वादी/अपीलांत द्वारा बिना किसी खातेदारी अधिकार के ही अधिनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी 1908 के प्रावधानों के अवलोकन किये जाने एवं उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर विधि के अनुरूप ही अपीलांत/वादी का वाद पत्र विधिक रूप से खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांत की अपील खारिज करवाई जावे।



उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 146 रकबा 0.43 है0 की खातेदारी के खाता संख्या 83 मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2073-76 में मूिमि रेस्प0के नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलांत/वादीगण का कथन रहा कि विवादित आराजीयात पर कब्जा अपीलांत/वादीगण का है परन्तु अपीलांत/वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादित आराजीयात पर कब्जा उनका सिद्ध हो सके। विवादित आराजीयात की खातेदारी जरिये नामा0 संख्या 95 से रेस्प0/प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई। उक्त नामा0 संख्या 95 की कोई अपील वादी/अपीलांत द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करना स्वयं वादी/अपीलांत ने स्वीकृत किया है। उक्त नामा0 की जानकारी वादी/अपीलांत को पूर्व से ही थी। फिर भी उनके द्वारा उसके विरुद्ध कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। चूकि विवादित आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073-76 में रेस्प0/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी 1908 के प्रावधानों के तहत ही वादी/अपीलांत का वाद पत्र विधि से वर्जित होने के कारण एवं वादी/अपीलांत का वाद पत्र सीपीसी के प्रावधान आदेश 7 नियम 11 से प्रभावित होने के कारण वाद पत्र विधि की प्रक्रिया के तहत ही खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांत की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांत खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 44/18 में पारित निर्णय दिनांक 18.5.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.6.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्रधिकारी
सवाई माधोपुर